Scholarships amounts to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students was much more delayed during the last year by the State Governments than in the previous years; and

(b) whether the scholarships were disbursed last year at the Central Government or at the State Government rate?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) Yes, Sir, in some cases.

(b) Scholarships were paid at the Central rates by all the State Governments except by the Government of Bihar from whom a clarification is awaited.

रूरकेला इस्पात कारखाना

*४५७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जर्मन इंटरनेशनल" में प्रकाशित उस लेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें रूरकेला इस्पात कारखाने में त्रुटियों के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में तथ्य क्या है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

लेख में इस बात पर आलोचना की गई है कि देश में इस्पात के तेजी से उत्पादन का लक्ष्य देश में तकनीकी व्यक्तियों की कमी को ध्यान में रखे बिना ही किया गया है। यह तो सच है कि देश में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है परन्तु इस्पात के मौजूदा कारखानों और तीसरी पंच-वर्षीय योजना में चालू होने वाले कारखाने के लिये उपयुक्त भारतीयों के प्रशिक्षण के प्रयत्न किये जा रहे हैं। व्यक्तियों के प्रशिक्षण के साथ साथ इस्पात कारखानों को चालू करने के संग न सम्बन्धी कार्यों का भी प्रबन्ध किया जा रहा है और इस कार्य में किसी विशेष कठिनाई के आने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

रूरकेला इस्पात प्रायोजना की प्रारम्भिक अवस्था में यातायात की समस्या अवश्य उत्पन्न हो गई थी। १९५७-५८ की सर्दियों में कुछ सामान जमा हो गया था। इन कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया और बन्दरगाह से कार्यस्थल तक उपकरणों के यातायात के प्रबन्ध कर लिये गये हैं। यातायात की कठिनाइयां दूसरे कारखानों में भी अनुभव की गई थी तथा इतने विशाल कारखाने में ऐसी कठिनाइयों का आ जाना अनिवार्य है। कारखाने की नीवें रखने के काम में भी कुछ विलम्ब हो गया क्योंकि कंक्रीट की बड़ी मात्रा इनमें लगी। यह भी सत्य है कि स्थानीय भारतीय फर्मों को इस प्रकार के काम का अधिक अनुभव नहीं था। लेकिन इन कठिनाइयों पर भी काबू पा लिया गया और इतने पर भी भारतीय फर्मों ने अच्छा कार्य किया।

लेख में रूरकेला के प्रबन्ध के बारे मे चर्चा की गई है। यह प्रबन्ध इस समय जर्मनी की दो फर्मों—क्रप और डेमाग—के पास है। यह फर्में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के परामर्शदाता के रूप में कार्य करती हैं। इन्होंने प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया जिसके आधार पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने जर्मनी की ३० प्रसिद्ध फर्मों से इस्पात कारखाने के लिए उपकरणों की सप्लाई करने और कारखाने के विभिन्न भागों में इनको लगाने के लिये ठेकों के प्रबन्ध किये। इन प्रबन्धों में कोई अन्तर्भूतीय कमी नहीं है और हर एक पार्टी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट हैं।

जबकि "पैकेज डील" में कुछ लाभ होते हैं जैसा कि दुर्गापुर और भिलाई के सम्बन्ध में हुआ है यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि रूरकेला के सम्बन्ध में भी ये समान रूप से लाभप्रद होंगे। लेख में भी इस बात का संकेत है कि इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत हैं। प्रारम्भिक कठिनाइयों के अलावा चालू इकाइयों के स्थापन कार्यों में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे इस लिये हैं कि कार्य प्रारम्भिक है और समय समय पर जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उन पर यथा सम्भव तेजी के साथ काबू पा लिया जाता है।

रूरकेला इस्पात कारखाने की विभिन्न इकाइयों को चालू रखने के लिये पुर्जों का काफी मात्रा में संग्रह करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है। मरम्मत करने वाले कारखाने में भी आवश्यक मशीनरी लगाई जा रही है जिस से यह अपना कार्य सूचक रूप से कर सके।

"जर्मन इन्टरनैशनल" में प्रकाशित लेख में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की इतनी आलोचना नहीं की गई है जितना कि उन कठिनाइयों का विषलेषण है जो कि उस देश में उत्पन्न हो जाती हैं जिस में इस्पात बनाने जैसा साहस पूर्ण कार्य प्रारम्भ किया जाता है। तथ्य तो यह है कि यह लेख इतनी बड़ी कठिनाइयों के बावजूद भी इस्पात के तीन संयंत्रों के लगाने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा है।

Public Undertakings

*458. **Shri Morarka:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government has considered the recommendation of the Estimates Committee in their 20th and 60th Reports that for all public undertakings a performance and programme statement for the budget year together with the previous year's statement should be made available to Parliament at the time of the annual budget; and

(b) if so, what decision has been taken in the matter?

The Deputy Minister of Finance (Shrimati Tarkeshwari Sinha): (a) and (b). The question will be answered by the Minister of Commerce and Industry on a subsequent date.

Journal of Nain Singh

*459. **Shri H. N. Mukerjee:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the original journals (in Hindustani) of Nain Singh (often called 'the Pandit'), a great Indian explorer of the Himalayan region who some time after 1874 got the Gold Medal of the Royal Geographical Society, are available in the National Archives; and

(b) if so, whether he will examine the desirability of publishing the said journals?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): (a) Yes, Sir.

(b) Some extracts from the original Diary have already been translated and published. The whole text in Hindi is likely to be published by the Sahitya Akademi.

Indian Institute of Technology, Kanpur

*460. **Shri Subodh Hansda:**
Shri R. C. Majhi:
Shri Nek Ram Negi:
Shri Kalika Singh:

Will the Minister of **Scientific Research and Cultural Affairs** be pleased to state:

(a) whether any final decision has been arrived at between the Government of India and the Government of the U.S.A. as to the nature and scope of assistance provided by the U.S.A. Government to the Indian Institute of Technology, Kanpur; and

(b) if so, the details thereof?